an>

Title: Need to enhance to honorarium of Accredited Social Health Activists under National Rural Health Mission in the country.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) ः भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं हेतु ""मातृत्व लाभ योजना"" आशा बहुओं के माध्यम से केंद्र सरकार ने पूरे देश में लागू कर रखी है जिसके परिणामस्वरूप मातृत्व एवं शिशु की मृत्यु दरों में कमी आयी है। पूरे देश में लगभग आठ लाख आशा बहुएं जच्चा-बच्चा की सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु कार्य कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं को आशा बहुओं द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा जिला अस्पताल ले जाकर प्रसव से पूर्व कम से कम तीन बार उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराने का कार्य कराया जाता है। उसके उपरान्त सुरक्षित डिलीवरी करने के लिए आशा बहुएं गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाती हैं। आशा बहुओं द्वारा जननी स्वास्थ्य सुविधाओं की जिम्मेदारी निभाने के बावजूद मात्र 600 रूपए प्रति केस अनुमेय है। देश, विशेषकर उत्तर प्रदेश में विगत एक वर्ष से आशा बहुओं को प्रोत्साहन राशि भी मिलने में कठिनाई हो रही है जिसके कारण उनके समक्ष जीविकोपार्जन का काफी गंभीर संकट पैदा हो गया है जबकि आशा बहुएं लगातार प्रोत्साहन राशि की एवज में 3 हज़ार रूपए प्रति माह मानदेय दिये जाने की मांग को लेकर संघर्ष कर रही हैं।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि आशा बहुओं के गर्भवती महिलाओं के प्रति समर्पण को देखते हुए भारत सरकार द्वारा उन्हें 3 हज़ार रूपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाना चाहिए।